

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 18 जनवरी 2024 गुरुवार

सम्पादकीय

एकला चलो रे की राह पर मायावती

मायावती ने आगामी लोकसभा चुनावों में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करके भले ही विपक्षी इंडिया गठबंधन को चौंकाया हो, लेकिन इस बात के कयास पहले ही लगाए जा रहे थे। हाल के दिनों में राजग की शीतली-नीतियों को लेकर जिस तरह का उदार रवैया बसपा सुप्रिमो दिखा रही थीं, उससे भी ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे थे। यहां तक कि पिछला लोकसभा चुनाव उन्होंने जिस सपा के साथ लड़ा था, उसके मुखिया को उन्होंने रंग बदलने वाला गिरगिट तक कह दिया। मायावती ने कहा कि जिन दलों के साथ बसपा ने पिछले चुनावों के दौरान गठबंधन किया था, उनके वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होते। बहरहाल, मायावती के एकला चलो रे फैसले से इंडिया गठबंधन को झटका जरूर लगा है, खासकर देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी को आस थी कि मायावती विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनेंगी तो वोटों का विखराव रोका जा सकेगा। खासकर दिल्ली की कुर्सी का रास्ता दिखाने वाले उत्तर प्रदेश में बड़त लेने के लिये, जहां वंचित समाज में पार्टी की मजबूत पकड़ रही है। जहां तक मायावती के वोट ट्रांसफर न होने वाले आरोप का सवाल है तो अन्य विपक्षी दल इस आरोप से सहमत नहीं हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उ.प्र. में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 1993 व 2019 में विधानसभा व लोकसभा के चुनाव लड़े थे। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि वर्ष 1993 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा में वोट ट्रांसफर हुआ था। जिसके चलते राज्य में गठबंधन की सरकार बनी थी। हालांकि, वर्ष 2014 में सपा-बसपा अलग-अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन वर्ष 2019 में दोनों साथ मिलकर लड़े। इससे दोनों दलों को फायदा हुआ। यहां तक कि बसपा को ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि 2014 में भाजपा के राजनीतिक गणित से मात खाकर बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। जबकि गठबंधन के साथ बसपा 2019 में दस लोकसभा सीट पाने में सफल रही। हालांकि, सपा को ज्यादा लाभ नहीं हुआ, उसके खाते में सिर्फ पांच लोकसभा सीट ही आईं।

बहरहाल, कतिपय राजनीतिक पंडित मानकर चल रहे हैं कि बसपा का अलग चुनाव लड़ने का निर्णय भाजपा को लाभ पहुंचाने वाला है। यह भी राजग की लिखी पटकथा की ही हिस्सा है। यहां तक कि सपा बसपा को भाजपा की बी टीम तक कहा करती थी। विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को सरकारी एजेंसियों के रडार में लाकर दुरुस्मरण चित्रित किया जाता रहा है। यह भी तथ्य है कि तमाम राजनीतिक दलों का अर्थास्त्र पाक-साफ तो नहीं ही रहता है। जिसके चलते ये ईडी व अन्य वित्तीय एजेंसियों की संभावित कार्रवाई की आशंका में दबाब में आ जाती हैं। विपक्षी दल बसपा के राजग को परोक्ष रूप से लाभ पहुंचाने की रणनीति को इसी दृष्टि से देखते हैं। यही वजह है कि बसपा ने भी उन तीनों-तल्ल नारों से परहेज किया है जो आक्रमक बहसवर्णों को लेकर उछालती रही है। अब मनुवाद के नाम पर निशाने पर लेने का क्रम भी टूटा हुआ नजर आता है। कभी बसपा संस्थापक काशीराम द्वारा बामसेफ व डीएस-4 जैसे संगठनों की स्थापना के बाद इसका राजनीतिक स्वरूप तन कर देने पर पार्टी के तेवरों में जो आक्रामकता होती थी, वह अब नदारद है। दरअसल, दलित-मुस्लिम गठजोड़ की वैचारिकी पर आधारित यह राजनीतिक दल कालांतर मुस्लिमों का भरोसा भी कायम न रख सका। एक समय पार्टी का उरोज इस कदर था कि 1987 के हरिद्वार लोकसभा उपचुनाव में दिग्गज दलित नेता राम विलास पासवान तक की जमानत जन्म हो गई थी। ये बसपा-सपा गठबंधन की ताकत थी कि 1992 में अयोध्या में विवादित दंडा गिराये जाने के बाद चली राम लहर में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं मायावती का जमापार अब इतना नहीं रह गया कि पार्टी किमेक की भूमिका निभा सके। उसके परंपरागत जनाधार पर मोदी कैम्पेडि ने संघ लगा दी है। बहरहाल, बसपा का अकेले चुनाव लड़ना भाजपा को रास आएगा क्योंकि इससे विपक्षी गठबंधन का जनाधार खिसकेगा। जिससे भाजपा की जीत की राह आसान हो सकती है।

धर्म—अध्यात्म की परम्परा और राजनीति



—निर्मल रानी—

श्री राम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या में श्राण प्रतिका १ समारोह 22 जनवरी को होना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ व उसके सहयोगी संगठन तथा भारतीय जनता पार्टी व अन्य की केंद्र व राज्य की सरकार इस आयोजन को न केवल राष्ट्रीय अभिषु अभूतपूर्व व भव्य बनाने के लिये दिन रात काम कर रही हैं। इस आयोजन में सुप्रिम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार द्वारा बनाये गये 15 सदस्यीय ट्रस्ट, विशेषकर इस ट्रस्ट के भी निर्णय लेने की क्षमता रखने वाले कुछ लेखन युगे मंदिर ट्रस्ट के सदस्य सक्रिय है या फिर स्वयं प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कार्यालय इस आयोजन की सीमा गिराणी कर रहा है। इस आयोजन में अरबों रुपये खर्च होने का अनुमान है। उधर धार्मिक अणुधनाकर कहे जाने वाले इस पूरे आयोजन में हमारे देश के चार प्रमुख शंकराचार्यो इस ऐतिहासिक व धार्मिक आयोजन पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुये इसमें शामिल न होने का



निर्णय लिया है। वैसे तो ओडिशा के पुरी में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, गुजरात में द्वारकाधाम में शांदा मठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती, उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तथा दक्षिण भारत के रामेश्वरम् में श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जगद्गुरु भारती तीर्थ सस्मी शंकराचार्यो ने सार्वजनिक तौर पर अपनी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुये इसके कई अलग अलग कारण बताये हैं। परन्तु इनमें सबसे महत्वपूर्ण व विस्तृत साक्षात्कार बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा सुनिश्चित पत्रकार करण थापर को दिया गया।

काविले गोल है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ व उसके सहयोगी संगठन व भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के दौरान

प्रायः कुंभ मेलों के दौरान या अन्य अवसरों पर देश के साबु संतों द्वारा आयोजित विशाल मठ मसंमद को अपने मंदिर आंदोलन का न केवल अनुआकार बल्कि मंदिर निर्माण व आंदोलन सम्बन्धी सभी निर्णय लेने वाला संगठन बताती थीं। मंदिर आंदोलन के दौरान अक्सर यह सुनाई देता था कि मंदिर या आंदोलन सम्बन्धी फैसले संत समाज ही करेगा। परन्तु नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद तो गोया भाजपा व संघ ही न केवल देश बल्कि धर्म सम्बन्धी भी निर्णय अपनी इच्छा व राजनैतिक नफे नुकसान के अनुसार लेने लगा। यही तक कि चारों शंकराचार्यो के अनुसार संतों से हिन्दू धर्म के सबसे प्रमुख आराध्य भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा सम्बन्धी किसी भी तरह की परिसर्वा करना तक मनासिब नहीं समझा गया ? और जब इन्हीं शंकराचार्यो ने प्राण

प्रतिष्ठा के मुहूर्त के समय को लेकर और अग्रे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किये जाने को लेकर तमाम सवाल खड़े किये तो 'पेशेवर दोलर' व 'दरबारी मीडिया' द्वारा इन्हीं सम्मानित शंकराचार्यो पर तरह तरह के लांछन लगाये जाने लगे ? यहाँ तक कि भगवान राम को लेकर संतों के सम्प्रदाय तक पर बहस छेड़ दी गयी? उनकी कारगुजारियों पर सवाल खड़े होने लगे ? उन्हें कांग्रेसी बताया जाने लगा ? यहां तक कि चारों पीढ़ों के वास्तविक शंकराचार्यो के जिवन में फर्जी शंकराचार्य व पीठा धिक्कर तक बयानबाजी के लिये उतार दिए गये ? किसी के पास शंकराचार्यो के इस सवाल का जवाब नहीं कि अग्रे मंदिर में मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है ? शंकराचार्यो के अनुसार केवल मंदिर का गर्भगृह तैयार होना मात्र पर ही मूर्ति स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल

नहीं की जा सकती। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तो 22 जनवरी की तिथि का मुहूर्त निकालने को ही चुनौती देते हुये कहते हैं कि मठ को जितने भी पंचांग प्रकाशित होते हैं जिनमें पूरे वर्ष के शुभ मुहूर्त का उल्लेख होता है उनमें किसी भी मठ 22 जनवरी की तिथि को विशेष मुहूर्त के रूप में प्रकाशित नहीं किया है। उन्होंने यह भी बताया की काशी के एक प्रतिष्ठित ज्योतिषी से यह कहा गया कि जनवरी माह में ही कोई शुभ मुहूर्त देखकर तिथि बताये लिखा ज्योतिषी जी ने खाइया पालन किया। अब सवाल यह है कि मंदिर भी अग्रे, शुभ मुहूर्त भी ऐसा नहीं जिसे कहा जाये कि यह पांच सदियों से प्रतीक्षारत भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का अति विशिष्ट मुहूर्त हो ? फिर आखिर यह आयोजन पूर्णतः राजनैतिक आयोजन नहीं तो इसे क्या कहा जाये ? और जब शंकराचार्य जिन्हें बुलाया गया वे जा नहीं रहे और कुछ को बुलाया भी नहीं गया, कोई कर रहे हम ताली बजाने के लिए नहीं जायेंगे, ऐसे में कांउंस, सोनिया गाँव, खडगें, अखिलेश या कम्युनिस्टों अथवा अन्य नेताओं के पीछे पड़ना या उन्हें राम विरोधी बताकर बिकाऊ मीडिया के हथौथे उनके विरुद्ध मीडिया ट्रोलर छेड़ना यह आखिर कैसा लज्जाजनक फैसला है? उनसे कहें कि राजनीति तो कैसा धर्म ?

भगवान राम के मंदिर का आयोजन वास्तव में ऐसा होना चाहिये कि न केवल संत साबु संत बल्कि सभी धर्म व समुदायों के लोग, सभी राजनैतिक व सामाजिक दलों के

लोग भी खुशी खुशी इस पावन क्षण के साक्षी बनें उसके भागीदार बनें। बजाये इसके बहुमत के नशे में मदमस्त वर्तमान सत्ता ने इस ऐतिहासिक अवसर पर शंकराचार्यो तक को आदर सम्मान व अहमियत कुछ भी नहीं दिया। यदि राजनीति के घाणव्य इस बात पर खुश होंगे कि इतिहास में यह लिखा जायेगा कि श्रम लला को कौन लाया था ? तो उसी इतिहास में साक्षी ही यह भी दर्ज होगा कि सत्ता के अहंकार व स्वाध्यापूर्ण राजनैतिक परिस्थितियों में ही जब रामलला विराजमान हो रहे थे तो उनका भवन (मंदिर) अग्रे था। और यह भी कि उनके आगमन के समय फिल्मी दुनिया के लोग, उद्योगपति, खिलाड़ी, नेता आदि तो उपस्थित थे परन्तु चारों शंकराचार्य विरोध स्वरूप अनुपस्थित थे। और यह भी कि उनके राजनैतिक सामाजिक दलों ने इस आयोजन का बहिष्कार केवल इसलिए किया था कि इस सामाजिक आयोजन को पूरी तरह 'राजनैतिक आयोजन' बना दिया गया था। स्वयं शंकराचार्यो का अनुमान है कि अग्रे मंदिर को पूर्ण रूप से तैयार होने में एक वर्ष और लग सकता है। और यह भी कि भगवान राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिये भगवान राम से अर्चना दिव व मुहूर्त और कौन सा हो सकता है ? परन्तु राजनैतिकों की किसी आत्ति या सुझाव पर विचार करने वाला कोई नहीं है। उसके बाद भी श्रम रास व रम्पाना के बाद हस्तक्षरपन नहीं तो और क्या? इस तरह की सत्तापक व स्वाध्यापूर्ण राजनीति नित्य में धर्म, धर्माचार्यो, अध्यात्म व परम्पराओं को चुनौती दी दे सकती है।

सांप्रदायिकता हमारी मनुष्यता को भी चुनौती



—विश्वनाथ सचदेव—

अब राहुल गांधी पूर्व से पश्चिम की यात्रा पर हैं। उनकी पिछली यात्रा 'भारत जोड़ो यात्रा' के नाम से हुई थी। उस यात्रा के परिणामस्वरूप भारत कितना जुड़ा इसका कोई अकलन अभी हुआ नहीं है। हा, इस यात्रा से राहुल गांधी की छवि अवश्य कुछ सुधरी है। हो सकता है अब पूरव-पश्चिम यात्रा 'भारत जोड़ो यात्रा' से उनकी छवि कुछ और सुधरे। अभी तो शुरूवात है, आगे-आगे देखिये होता है क्या। लेकिन इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि इस दूसरी यात्रा का कदम आगे बढ़ाने में कांग्रेस से कुछ देरी अवश्य हो गयी है। पिछली यात्रा वाला जोश और उसे तन मिला प्रतिसाद अब दिखेगा या नहीं पता नहीं।

इस तरह की यात्राओं को नाम कुछ भी दिया जाये, उनके राजनैतिक उद्देश्य को नकारा नहीं जा सकता। लागूगती दशक पहले लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक रथ-यात्रा प्रारंभ की थी। उस यात्रा का घोषित उद्देश्य अयोध्या में 'भय-द्विज राममंदिर' की स्थापना कहा गया था। आज वह मंदिर बन चुका है। लेकिन क्या यही उद्देश्य था उस यात्रा का? इन तीनों दशकों में देश की राजनीति में भाजपा का जो स्थान बना है, उसमें लालकृष्ण आडवाणी की रथ-यात्रा के योगदान को नकारना देश की राजनीति और देश के मूढ़ को न समझना ही होगा। यह तब भी किसी से छिपी नहीं है कि तब अयोध्या के राम-मंदिर को राजनीति से जोड़ने की बात भाजपा के नेतृत्व ने छिपाने की कोशिश भी नहीं की थी। अयोध्या में भय राम मंदिर की स्थापना इस देश की आस्था से जुड़ी है। इस की असीम प्रशिक्षित आबादी के आस्था है श्रौरा। राम मंदिर का निर्माण इस आबादी के विश्वासों-निष्ठाओं का एक अभिव्यक्ति भी है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अयोध्या में आज जो कुछ हो रहा है, उसका राजनीतिक लाभ भी संभावित पक्षों को मिलेगा। सपा नहीं है कि कांग्रेस इस बात को समझती नहीं थी, पर उसे समझकर



हमने अपने संविधान में पंथ-निरपेक्षता को एक आदर्श के रूप में स्वीकारा है। इसका अर्थ आध्यात्मिक होना नहीं, सब धर्मों का समान सम्मान देना है। एक तरफ धर्म-निरपेक्षता हमारा आदर्श है तो दूसरी ओर सर्वधर्म समभाव भी हमारा राष्ट्रपति, हमारा प्रधानमंत्री, हमारे राजनेता, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध आदि धर्मों में विश्वास करने वाले हो सकते हैं, पर हमारे शासन का कोई धर्म नहीं है, शासन की दृष्टि में सब धर्म समान हैं। समान होने चाहिए। धर्म को राजनीति का हथियार बनाने का मतलब सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है, और सांप्रदायिकता हमारी मनुष्यता को भी चुनौती है।

आवरण कदम उठाने में सह विरक्त हो गयी है। बेहतर होता कांग्रेस राम मंदिर के न्यासियों का निमंत्रण स्वीकार करती, समारोह में जाती और साथ ही इस मामले के राजनीतीकरण का विरोध भी करती। इस राजनीतीकरण की आलोचना यह अवश्य कर रही है, पर इसका राजनीतिक लाभ उठाने वालों के जिस को पुरा न होने देने के लिए इसका राजनीतिक बहुराई की आवश्यकता अपेक्षित है, देश की सबसे पुरानी पार्टी में इसका अभाव स्पष्ट दिखा रहा है। राहुल गांधी की पूर्व-पश्चिम यात्रा यात्रा में विलंब और जोर में कभी भी इस अभाव को प्रदर्शित करती है।

हमने अपने संविधान में पंथ-निरपेक्षता को एक आदर्श के रूप में स्वीकारा है। इसका अर्थ आध्यात्मिक होना नहीं, सब धर्मों का समान सम्मान देना है। एक तरफ धर्म-निरपेक्षता हमारा आदर्श है तो दूसरी ओर सर्वधर्म समभाव भी हमारा राष्ट्रपति, हमारा प्रधानमंत्री, हमारे राजनेता, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध आदि धर्मों में विश्वास करने वाले हो सकते हैं, पर हमारे शासन का कोई धर्म नहीं है, शासन की दृष्टि में सब धर्म समान हैं। समान होने चाहिए। धर्म को राजनीति का हथियार बनाने का मतलब सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है,

और सांप्रदायिकता हमारी मनुष्यता को भी चुनौती है। अयोध्या में भगवान राम के भय-द्विज मंदिर के निर्माण का देश की जनता ने स्वागत ही किया है। इस संदर्भ में कुछ मुद्दे पर मन्थन हो सकते हैं, पर आज जो वातावरण में बना है वह सकारात्मक ही दिख रहा है। जरूरी है कि सकारात्मकता को बनाये रखा जाये। धर्म को राजनीतिक करने वालों को इस बात को समझना होगा कि सारे मन्थनों के बावजूद अयोध्या में रहने वाले मुसलमान मंदिर के निर्माण को लिये आवरण कदमों की व्यवस्था में भी योगदान दे रहे हैं। इस बात को नही भुलाया जाना चाहिए पूजा के फूल हो या मूर्तियों को पहनने वाले धार वस्त्र, इनका माध्यम भी मुख्यतः वहां के मुसलमान ही रहे हैं। यही नहीं देश में अनेक स्थानों पर मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए जाने वाले कोष में भी मुसलमानों ने योगदान दिया है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कितना दिया गया, महत्वपूर्ण यह है कि योगदान किया गया। आसानी से संयोग की यह भ्रमना बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि अग्रे मंदिर-निर्माण का राजनीतिक लाभ उठाने की कोई कोशिश न हो। धर्म के नाम पर देश के मतदाताओं को बांटा न जाये।

यह बात कहना आसान है और ऐसे बातें करना भी तलत नहीं है। पर हकीकत यह भी है कि आज हमारी राजनीति में ऐसे तलत है जिनके लिए धर्म आस्था का नहीं, वोट जुटाने का माध्यम है। इन तलतों से सावधान रहने की आवश्यकता है, और इन्हें अफसोस बनाने की ईमानदारी कोशिश करने की भी। धर्म हमारे सोच, हमारे जीवन को संवल देने के लिए है, राजनीतिक नफे-नुकसान का हिसाब-किताब करने के लिए नहीं। शासक इसी संदर्भ में यह कहा गया था कि देश के प्रधानमंत्री मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा जैसे आयोजन से न जुड़े तो बेहतर रहता। इस संदर्भ में एक और सुझाव भी आया है। अयोध्या में मस्जिद-निर्माण से जुड़े कुछ लोगों का प्रस्ताव है कि देश के प्रधानमंत्री यदि मस्जिद के शिलान्यास-कार्य से भी जुड़े तो इसके दूरगामी संकेत होंगे- स्वागत योग्य संकेत।

सिर्फ भारत-जोड़ो कहने से बात नहीं बनेगी, भारत की एकता को मजबूत बनाने और बनाये रखने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर भारत-हित के बारे में सोचना होगा। बात बाहे राहुल गांधी की यात्रा की हो या फिर प्रधानमंत्री के जगह-जगह जाकर राष्ट्र की एकता की दुहाई देने की, जरूरी यह है कि हमारी राजनीति अपने स्वाध्य के लिए धर्म को जोड़ने की कोशिश ही अनेक आम में गत है। धर्म जीवन को संवरने का माध्यम है इसे सत्ता की राजनीति से जोड़ने अपने आप में एक पाप है, एक अपराध है। रुकनी चाहिए यह प्रक्रिया। अपराध की सजा मिलनी चाहिए और पाप का प्रायश्चित्त भी चाहिए। अपनी-अपनी आस्था के नाम पर राजनीतिक स्वाध्यों की सिद्धि का समर्थन नहीं किया जा सकता। नहीं किया जाना चाहिए।

बिना चार्ज किए 50 साल तक चलेगी बैटरी



चीन के एक स्टार्टअप ने एटोमिक पावर वाली बैटरी बनाई है। कंपनी का दावा है कि ये बिना चार्जिंग बैटरी नेक्सेस के 50 साल तक पावर देगी। इस बैटरी का साइज महज एक सिक्के के बराबर है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बीजिंग के बीटावोल्ट स्टार्टअप इस मॉड्यूल में 63 आइसोटोप को कंप्रेस करने में कामयाब रहा है, जो एक सिक्के से भी छोटा है। कंपनी ने ये भी कहा कि ये एटॉमिक एनर्जी को सबसे छोटा रूप देने वाली दुनिया की पहली बैटरी है। कंपनी का दावा है कि न तो इस बैटरी में आग लगेगी और न ही दबाव पड़ने पर इसमें विस्फोट होगा, क्योंकि अलग-अलग तामपान पर इसका परीक्षण फेज में है। जल्द ही मोबाइल फोन और ड्रोन जैसे इविकपमेंट्स के लिए बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन किया जाएगा।

कंपनी ने कहा कि, बीटावोल्ट एटॉमिक एनर्जी बैटरिज एरोस्पेस, एआई इविकपमेंट्स, मेडिकल इविकपमेंट्स, माइक्रोप्रोसेसर, एडवांस्ड सेंसर, स्मॉल ड्रोन और माइक्रो रोबोट जैसे कई इविकपमेंट्स में लंबे समय तक पावर प्रसार्दी कर सकती है। ये बैटरी खासतौर पर एआई की दुनिया में क्रांति लाने का काम करेगी।

बैटरी का डायमेंशन 15x15x5 सेमीएम है। ये परमाणु आइसोटोप और हीरे के सेमीकंडक्टर की पतली परतों से बना है। परमाणु बैटरी वर्तमान में 3 वोल्ट पर 100 माइक्रोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। कंपनी की प्लानिंग है कि 2025 तक इसे 1 वॉट की पावर पर ले जाए। बीटावोल्ट का कहना है कि ये पतली न्यूक्लियर बैटरी है, जो 100 माइक्रोवॉट की पावर जनरेट करती है।

कैसे काम करती है बैटरीये बैटरी आइसोटोप से निकलने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलने का काम करती है। पहली बार इस प्रक्रिया को 20वीं सदी में विकसित किया गया था। सोवियत संघ और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मिलकर ये कॉन्सेप्ट तैयार किया था। वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का इस्तेमाल अंडरवॉटर सिस्टम और रिमोट साइटिफिक स्टेशन में किया था। हालांकि, इसकी लागत ज्यादा आ सकती है और प्रोडक्शन के बाद ये महंगी बैटरी हो साबित सकती है। — कुसुम

[illegible]

